



स्वस्थ संबंधी किताबों को पढ़ने में सावधानी बरतिए। एक मुद्रणदोष की वजह से आपकी मौत हो सकती है।

-मार्क ट्वेन

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

● वर्ष: 12 ● अंक 237 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, सोमवार 5 अक्टूबर, 2026

पाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म... **6** कांग्रेस में चल रहा सुलह व कलह... **3** सीट बंटवारे को लेकर सपा व कांग्रेस... **2**

राहुल गांधी ने 4PM पत्रकारों को बुलाकर जाना दिल का हाल, संघर्ष को किया सलाम

मुस्लिम होने का पता चला तो पुलिस की पिटाई और बढ़ी!

» दिल्ली पुलिस की हैवानियत मुस्लिम पता चलने के बाद बढ़ गयी पत्रकारों की पिटाई
» शाहीन-नफीसा से मिले राहुल गांधी पूछा दर्द का हाल 4PM की लड़ाई को मिला बड़ा मुकाम

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। कभी कभी मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती वह महीनों से चल रही लड़ाई के बीच अचानक आई ऐसी रोशनी होती है जिसमें पीछे छूटी पूरी कहानी फिर दिखाई देने लगती है। जी हां 4PM की पत्रकार शाहीन और नफीसा लिए आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। आज उनसे जन-जन की आवाज बन चुके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात कर पूरी घटना को जाना और उनका हौसला बढ़ाया।

राहुल गांधी ने मुलाकात के इन क्षणों को देश की जनता के साथ वीडियो बना कर शेयर भी किया। आज का दिन निश्चित तौर पर 4PM के लिए विशेष दिन है क्योंकि आज रिपोर्टिंग के दौरान जिस घटनाक्रम ने दोनों पत्रकारों को दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा कर दिया था उसी घटना की पीड़ा और संघर्ष की कहानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जानी। आज की मुलाकात को उस महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है जो 3 सितंबर को दिल्ली के साकेत थाने से शुरू हुआ और उसके बाद लगातार देशभर में चर्चा का विषय बना। क्योंकि उस दिन सिर्फ दो पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला नहीं उठा था। सवाल उठा था क्या सवाल पूछने वाले पत्रकार को रोका जा सकता है और उससे भी गंभीर सवाल क्या किसी पत्रकार की धार्मिक पहचान सामने आने के बाद उसके साथ व्यवहार बदल सकता है।



राहुल की मुलाकात पत्रकारिता का सवाल भी

इस मुलाकात को सिर्फ राजनीतिक चरने से देखना पूरी कहानी को छेदा कर देगा क्योंकि राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष होना राजनीतिक तथ्य है लेकिन शाहीन और नफीसा से उनकी मुलाकात का दूसरा पहलू पत्रकारिता से जुड़ा है। एक पत्रकार जब किसी मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है तो वह किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता। वह सवाल पूछता है क्योंकि जनता के पास सवाल है। यही लोकतांत्रिक पत्रकारिता का मूल है। और अगर किसी पत्रकार के साथ पुलिस की कार्यवाही को लेकर विवाद पैदा होता है तो सवाल सिर्फ उस पत्रकार के लिए नहीं रह जाता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

से 4PM के पत्रकार नफीसा/शाहीन की मुलाकात उनके आफिस में हुई जहां उन्होंने दोनों पत्रकारों की रुतब बहुत इत्मीनान के साथ सुनी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह इस पूरे प्रकरण को देखेंगे। आधे घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मुलाकात में राहुल गांधी ने दोनों पत्रकारों से तमाम सवाल पूछे जैसे कि किस हॉस्पिटल का उद्घाटन था? एस्पएओ कौन था? जिस महिला पुलिसकर्मी ने पत्रकारों के साथ अश्रद्धा की उस महिला अधिकारी का नाम क्या था। उन्होंने पूछा कि पुलिस ने आप को मार कैसे? उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि मारपीट का पूरा

व्या है? उन्होंने शाहीन/नफीसा से यह भी पूछा कि आप का केस कौन लड़ रहा है। राहुल गांधी बहुत ही आलीशान से दोनों पत्रकारों से मिले और शाबाशी दी। शाहीन/नफीसा ने राहुल गांधी को बताया कि वह बस यह चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने सरकार से यह पूछा है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया तो वह यह भी पूछे कि हम दोनों के साथ उत्पीड़न करने का आदेश, थाने में मारने का आदेश, धर्म पूछ कर सजा बड़ा देने का आदेश किसने दिया? दोनों पत्रकार राहुल गांधी को अपनी अपबीती सुनाते समय कई बार भावुक हुईं।

राहुल गांधी की मुलाकात ने 4PM की लड़ाई को नयी ऊर्जा प्रदान की : संजय शर्मा

राहुल गांधी की मुलाकात से 4PM के भीतर स्वाभाविक तौर पर खुशी और गर्व का माहौल है। लेकिन संस्थान के संपादक संजय शर्मा के लिए यह भावनात्मक क्षण भी है। शाहीन और नफीसा के साथ हुई घटना के बाद उन्होंने जिस तरह संस्थान के स्तर पर दोनों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी वह कबीले तारीफ भी है और काबीले नज्दी भी है। घटना का पता चलते ही वह फौरन दिल्ली पहुंचे और संघर्ष की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने हर उस स्तर पर अपनी बात रखी जो दिल्ली सरकार तक पहुंचे। उन्होंने इस पूरे उत्पीड़न को अपनी लड़ाई माना। आज राहुल गांधी की मुलाकात को वह उस संघर्ष के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखते हैं। संजय शर्मा ने कहा है कि वह हमेशा पत्रकारों के हित के साथ खड़े रहे हैं और शाहीन तथा नफीसा की लड़ाई संस्थान हर स्तर पर और हर संभव सीमा तक तब तक लड़ेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उनके लिए यह मुलाकात सिर्फ सम्मान का क्षण नहीं है। और उस पत्रकारिता की भी जो दबाव के बीच सवाल पूछने से पीछे नहीं हटती। नीडिया संस्थानों की जिदगी में ऐसे क्षण कम आते हैं जब किसी पत्रकार के व्यक्तिगत संघर्ष को देश के बड़े सार्वजनिक मंच पर पहचान मिलती है। शाहीन और नफीसा के लिए आज का दिन भी वैसा ही है।



आज की खुशी के साथ कल की लड़ाई बाकी है

वह कहते हैं कि 3 सितंबर को शाहीन/नफीसा के शरीर पर चोट के निशान थे आज उनके साथ खड़े होने वाला एक बड़ा राजनीतिक चेहरा सामने है। उस दिन सवाल था हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ आज सवाल थोड़ा आगे बढ़ चुका है क्या पत्रकारों को सुरक्षित तरीके से सवाल पूछने का अधिकार मिलेगा और यही फर्क किसी घटना को बड़े मुद्दे में बदल देता है। वह कहते हैं कि जंग अभी बाकी है न्याय का सवाल अभी भी बाकी है। उनकी मान्यता है कि



किसके खिलाफ क्या कार्यवाई होगी? आरोपों की जांच कब तक पहुंचेगी? क्या सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या पत्रकारों की शिकायतों पर उचित कार्यवाई होगी के साथ सबसे जरूरी है कि क्या भविष्य में किसी पत्रकार को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उसका नाम धर्म या सवाल किसी को पसंद नहीं आया? इन सवालों के जवाब अभी बाकी है। इसलिए आज की खुशी के साथ कल की लड़ाई भी सामने है।

धार्मिक पहचान उजागर होने के बाद बढ़ा उत्पीड़न

शाहीन और नफीसा ने जो बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताई वहीं बात उन्होंने आज राहुल गांधी के साथ भी शेयर की। दोनों के आरोप दिल्ली पुलिस पर बहुत ही संगीन इतने संगीन कि आरोपियों को ताउम्र जेल में डाल दिया जाए वह भी कम। शाहीन/नफीसा ने राहुल गांधी से पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें हैरानी तब हुई जब साकेत थाने के पुलिसकर्मियों को पता चला कि वह मुस्लिम हैं। यह पता चलते हुए उनके साथ व्यवहार

बदल गया और उत्पीड़न के तरीके। माफ़ थली बेहद बेहूदा रहीं। राहुल गांधी ने दोनों पत्रकारों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी बलदूरी की तारीफ की और कहा कि देश को आप पर गर्व है कि आप ने न सिर्फ सच बल्कि उसका डट कर मुकाबला किया और पूरे देश को बताया कि दिल्ली पुलिस सरकार के



इशारे पर किस तरह का कार्य करती है। अब राहुल गांधी की मुलाकात इस पूरी कहानी में आज का दिन नया अय्याय लेकर आया है। राहुल गांधी ने शाहीन और नफीसा से मुलाकात की नेता प्रतिपक्ष ने दोनों का हाल जाना उनकी बात सुनी उनके संघर्ष की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया शाहीन और

नफीसा के लिए आज की मुलाकात उस लंबे घटनाक्रम के बीच सबसे अलग क्षण रहा। क्योंकि 3 सितंबर को वह पुलिस हिरासत और मारपीट की बात कर रही थीं। आज वे देश के नेता प्रतिपक्ष के सामने बैठकर अपनी कहानी सुना रही थीं। यानी रास्ता लंबा था साकेत से बाहर निकलने से लेकर थाने की कहानी तक शिकायत से लेकर सार्वजनिक बहस तक और अब नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय तक एक लड़ाई ने एक लंबा सफर तय किया है।

सीट बंटवारे को लेकर सपा व कांग्रेस में तकरार

» यूपी कांग्रेस प्रभारी का सपा नेता शिवपाल पर तीखा प्रहार
» सपा साफ मना कर दे गठबंधन नहीं करना है : राजेंद्र पाल गौतम
□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सपा सांसद शिवपाल सिंह यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटों की उम्मीद न करे। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि तो वह मना कर दें न, वह साफ कह दें कि उन्हें गठबंधन नहीं करना है। कम से कम बात तो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इस तरह के हल्के बयान देने की जरूरत क्या थी।

राजेंद्र पाल गौतम ने उन सपा नेताओं के दावों पर भी पलटवार किया, जिनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो फायदा हुआ, वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से मिला। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा था तो 2019 में सपा को सिर्फ पांच लोकसभा सीटें क्यों मिली थीं। सीट बंटवारे को लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि गठबंधन होने पर दोनों



सपा को 37 सीटें गठबंधन से मिलीं

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 2024 का चुनाव सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने लड़ा था। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सपा को 37 सीटें मिलीं और यह सिर्फ सपा की वजह से नहीं, बल्कि पूरे गठबंधन और राहुल गांधी की नेतृत्व का परिणाम था। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए

कहा कि उन्होंने करीब 4,500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मजदूरों, किसानों, वंचित वर्गों, बर्द्ध, नैकेनिक, कुली और समाज के हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की और उनके हक-अधिकार की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि 37 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से मिलीं, तो यह अखिलेश यादव और उनके नेताओं की गलतफहमी है।

अक्टूबर में ही हो सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि अक्टूबर में ही सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाए, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला करने की कोशिश होगी।

पार्टियां मिलकर चुनाव जीतेंगी और सरकार नहीं, जीत की बात कर रही है, चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पार्टियों का होता

है और जनता पार्टी को वोट देती है, उन्होंने कहा कि विचारधारा के मामले में कांग्रेस पूरे

राज्यसभा चुनाव : अखिलेश यादव उतारेंगे तीसरा प्रत्याशी

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। यानी, मंगलवार तक सभी दलों को अपने पते खोलने होंगे। इस चुनाव में विधानसभा सदस्य वोट डालते हैं। मौजूदा स्थितियों में अधिकतम 393-394 वोट ही पड़ सकते हैं। सपा ने अपने दो प्रत्याशियों प्रो. रामगोपाल यादव और रिलायंस समूह के कंसल्टेंट धनराज नाथवानी को मैदान में उतार दिया है। मौजूदा समीकरणों में अगर सपा दो और भाजपा आठ प्रत्याशियों तक सीमित रहती है, तो चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। किसी भी पक्ष से एक भी और प्रत्याशी उतारे जाने पर मतदान कराना होगा। एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 36 मत चाहिए। सपा का दावा है कि जितने विधायक अभी उसके समर्थन में हैं, उनके मत जोड़ लें तो तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए उसे महज 5 मतों की और व्यवस्था करनी होगी। इन



अतिरिक्त मतों के लिए सत्ताधारी गठबंधन के कुछ विधायक उसके संपर्क में हैं। सपा सूत्रों का कहना है कि सपा नेतृत्व ने तीसरे प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र तैयार करवा लिया है, भाजपा के प्रत्याशियों और उनकी संख्या सामने आने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। यानी, सपा के पते सोमवार को या बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को सामने आ जाएंगे।

फुटबॉल की तरह उठा-उठाकर फेंक रही थी पुलिस : भारद्वाज

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में इंडिया गेट के पास को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और उसके छात्र

» हिरासत में लिए जाने पर भड़के आप दिल्ली अध्यक्ष



संगठन 'एएसएपी' के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रही बसों को रोकने की कोशिश की। मुझे फुटबॉल की तरह उठा-उठाकर फेंक रहे हैं हिरासत में लिए जाने के दौरान दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, वे मुझे उठा-उठाकर फुटबॉल की तरह इधर-उधर फेंक रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, यहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, फिर भी वे अपने ही एसीपी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं और न ही एसीपी को गिरफ्तार कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ता उन बसों पर चढ़ गए, जिनमें हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा था। कुछ कार्यकर्ताओं ने बसों को बीच सड़क पर घेर लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है।

यूपी में महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने योगी सरकार पर साधा निशाना

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में रोजाना महिलाओं के खिलाफ अपराध के औसतन 182 मामले दर्ज हो रहे हैं। लखनऊ, चार अक्टूबर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ कथित अपराधों को लेकर रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित प्रदेश बन गया है।

मिश्रा ने एक बयान में दावा किया कि पिछले एक सप्ताह में बुलंदशहर, बस्ती, बांदा, सोनभद्र, कौशाम्बी, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ में नाबालिगों से दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के कई मामले सामने आए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सोनभद्र में 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की प्रसव के दौरान मौत होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह घटना नाबालिगों के खिलाफ अपराध के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। उन्होंने ललितपुर में पांच वर्षीय बच्ची और प्रयागराज में 10 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के आरोपों का भी जिक्र किया। आराधना ने कहा कि सवाल केवल इन घटनाओं का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का है। उनके मुताबिक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 66,381 मामले दर्ज हुए, यानी रोजाना औसतन करीब 182



मामले। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में दुष्कर्म के 3,516 और हत्या के 3,206 मामले दर्ज किए गए। मिश्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 30 सितंबर को एक आपराधिक मामले की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत की टिप्पणियों के बावजूद प्रदेश सरकार की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया, जब स्कूल से घर लौटती बच्चियां, पांच और 10 साल की बच्चियां तथा नाबालिग छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी है? मिश्रा ने कहा कि बेटियां डर में नहीं, सम्मान और सुरक्षा के साथ जीना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार बेटियों को स्कूल, सड़क और घर में सुरक्षा नहीं दे सकती, उसे जनता सत्ता से हटा देगी।

सपा के साथ गठबंधन का सशर्त रास्ता खुला : ओवैसी

» एआईएमआईएम वीफ बोले- मदरसों में जब लगे ताले तब अखिलेश रहे चुप
□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले के भिनगा स्थित जेल रोड मैदान में एआईएमआईएम की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सपा से अपनी शर्तों पर गठबंधन की बात कही और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एआईएमआईएम उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें, ताकि भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोका जा सके।



भाजपा पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि बाबा (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) को मस्जिदों और मदरसों से एलर्जी है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सपा उनकी शर्तों पर गठबंधन करना चाहती है तो वे तैयार हैं, अन्यथा पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर अपना परचम लहराएगी। ओवैसी ने स्थानीय मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि श्रावस्ती में जब मदरसों और मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे थे और उन्हें तोड़ा जा रहा था, तब न तो सपा विधायक इंद्राणी वर्मा ने इसका विरोध किया और न ही सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने। केवल मैनुपुरी/मैनुद्दीन खां ने इसका विरोध किया, जिसके कारण उन्हें सात दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा।

जम्मू-कश्मीर के दलों को लद्दाख से सीख लेकर एकजुट होना चाहिए : महबूबा

» पीडीपी नेता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर एक साझा मंच बनाना चाहिए
□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

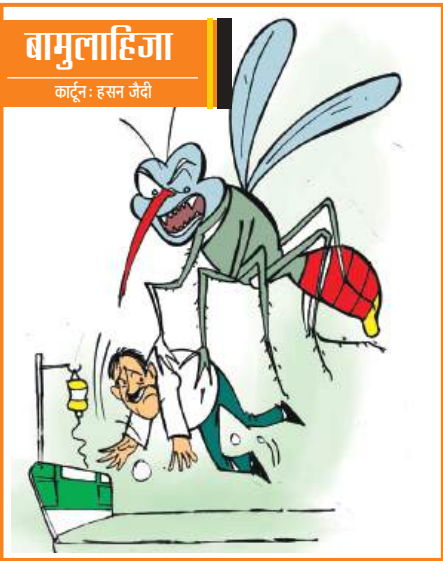
श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों से अपनी मांगों को आगे बढ़ाने में लद्दाख की एकजुटता से सीख लेने की अपील की। उन्होंने सभी दलों से एकजुट होकर क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को केंद्र के समक्ष



संयुक्त रूप से उठाने का आह्वान किया। महबूबा ने कहा, हमें लद्दाख से सबक लेना चाहिए कि वे किस तरह अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अकेले काम करने वाले

अलग-अलग राजनीतिक दलों के जरिए अपनी चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकता। पीडीपी नेता ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आकर एक साझा मंच बनाना चाहिए और केंद्र के समक्ष केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए। श्रीनगर में एक समाचार पोर्टल द्वारा आयोजित सम्मेलन के दौरान महबूबा ने कहा, "जब तक सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर दिल्ली के साथ बातचीत नहीं करते, तब तक हम उनसे यह नहीं कह पाएंगे कि हमारे संस्थानों पर प्रतिबंध

लگانा, छापेमारी करना और हमारे युवाओं को गिरफ्तार तथा हिरासत में लेना बंद करें। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती उसकी युवा आबादी से जुड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेताओं को केवल युवाओं के सवाल को जवाब देने के बजाय उनकी चिंताओं और मुश्किलों को समझने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने पहले ही सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर सभी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।



बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

कांग्रेस में चल रहा सुलह व कलह का दौर

पंजाब में एकजुटता की बात तो राजस्थान में संकट

» पूर्व मंत्री ने पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा को घेरा

» वडिंग के जाने के बाद पंजाब में एकजुटता की बात

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। राजस्थान व पंजाब की सियासी खबरें आजकल छाई हैं। दोनों राज्य में ये खबरें कांग्रेस से आ रही हैं। जहां पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन होने जा रहा है। वहां इसका क्रेडिट दिग्गज नेता सचिन पायलट को दिया जा रहा है वहां की समस्या का हल अर्थात पार्टी की गुटबाजी को दूर कराने में बड़ा योगदान रहा है।

पर इन सबके बीच उनके गृह राज्य राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस फिर कलह की खबरें कभी आ रही हैं। कांग्रेस चीफ डोटासरा पर पूर्व मंत्री के गंभीर आरोप और उनके परिवार को भी लपेटा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने लगातार दो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जहां निकाय चुनाव की हार पर पीसीसी चीफ डोटासरा पर हमला बोला। साथ ही उनके परिवार पर भी निशाने साधा।

विश्वेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने की चर्चा

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर के डोटासरा पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद सोशल मीडिया यह चर्चा होने लगी है कि क्या वे विश्वेंद्र सिंह भरतपुर भी कांग्रेस छोड़ अलग रास्ता अपना सकते हैं। वहीं उनके बीजेपी से जुड़ने को लेकर भी चर्चा तेज होने लगी है।



नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई खटपट

राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव और हाल ही संपन्न हुए निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के भीतर आंतरिक गुटबाजी और घमासान एक बार फिर दिखाई देने लगा है। हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई यह कलह अब व्यक्तिगत आरोपों और तीखे जुबानी हमलों तक आ पहुंची है। ताजा मामला राजस्थान के बृज क्षेत्र का है। यहां पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बुधवार को लगातार दो सोशल मीडिया पोस्ट के



जरिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भरतपुर-डीग के स्थानीय संगठन नेतृत्व पर सीधे हमले बोले।

विश्वेंद्र सिंह भरतपुर ने रखी डोटासरा के इस्तीफे की मांग

विश्वेंद्र सिंह ने डोटासरा के बयान में दिए गए कथित बयान भरतपुर में तो रास्ता पूछने के भी पैसे ले लेते हैं पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने इसे भरतपुर की जनता का अपमान बताते हुए कहा कि अगली बार डोटासरा के भरतपुर आने पर उनका विशेष स्वागत-सत्कार किया जाएगा। इन गंभीर आरोपों के साथ पूर्व मंत्री ने गोविंद सिंह डोटासरा

के इस्तीफे या फिर कांग्रेस आलाकमान से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। निकाय चुनाव की हार से भड़की यह चिंगारी अब आरएस, रीट और संगठन के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है। हालांकि, इन आरोपों पर फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा या पार्टी आलाकमान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

चुनावी प्रदर्शन को लेकर बोले थे राजा वडिंग

इससे पहले अगस्त में वडिंग ने पंजाब में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन को लेकर हुई आलोचना के खिलाफ अपना बचाव किया था और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के पतन के लिए अपने नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एकमात्र



गलती यह है कि जब कांग्रेस पार्टी के

पास 80 सीटें थीं, तो हम 80 से घटकर 18 सीटों पर आ गए। क्या यह मेरी गलती है? इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने उन्हें 2027 के चुनावों के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की मांग करते हुए नारे लगाए थे।

भूपेश की जगह सचिन पायलट बने प्रभारी

बता दें कि यह घटनाक्रम कांग्रेस द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को पंजाब के लिए पार्टी का महासचिव प्रभारी नियुक्त करने के बाद सामने आया है।



कांग्रेस पंजाब में अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही है,

जिसमें अलग-अलग गुट अगले विधानसभा चुनावों से पहले अधिक महत्व पाने की कोशिश कर रहे हैं। वडिंग को पहले भी पार्टी के कुछ वर्गों से अपने प्रदर्शन और नेतृत्व को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है।

जिलाध्यक्षों को ठहराया हार का जिम्मेदार

विश्वेंद्र सिंह ने सुबह भरतपुर-डीग कांग्रेस का बंटोधार- जिम्मेदार कौन शीर्षक से पहली पोस्ट जारी की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनावों में दोनों जिलाध्यक्षों ने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने



चहेतों को टिकट बांटे, जो कांग्रेस की हार का मुख्य कारण बना। उन्होंने कहा कि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जहां संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी था, लेकिन गलत फैसलों से पार्टी कमजोर हुई। डोटासरा पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री ने लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष इस पूरी व्यवस्था पर मूक-बधिर बनकर बैठे हैं और जब तक ये जिलाध्यक्ष पद पर हैं, तब तक पार्टी का उठना मुश्किल है।

सर्टिफिकेट पर जांच की मांग

अपनी दूसरी पोस्ट में पूर्व मंत्री ने गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार और रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से जांच की मांग उठाई। अपनी इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बीजेपी की ओर से लगाए जाने वाले पुरानी आरोपों को हवा दे दी है। उन्होंने 2016 और

2018 की आरएसएस भर्ती का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा पूनिया और उनके भाई-बहन गौरव व प्रज्ञा पूनिया को इंटरव्यू में एक समान (80-80) अंक मिले थे। विश्वेंद्र सिंह ने डोटासरा के पुत्र अविनाश सिंह के आरएसएस-2016 चयन में ओबीसी

नॉन-कीमी लेयर प्रमाण पत्र के इस्तेमाल और उनके समर्थी रमेश चंद पूनिया के परिवार को मिले लाभ पर भी सवाल उठाए। उन्होंने डोटासरा के शिक्षा मंत्री रहते हुए आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा फिर से उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वडिंग ने दिया इस्तीफा, 48 घंटे में होगा नए चीफ का एलान

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से राजा वडिंग के इस्तीफे की अटकलों पर विराम लग चुका है। लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार, पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट की रिपोर्ट और

आलाकमान के निर्देश के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के अनुसार, पंजाब में एक या दो दिन के भीतर कांग्रेस नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। अध्यक्ष पद की रेस में विजय इंदर सिंगला, परगट सिंह, सुखविंदर रंधावा और

चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं। इस लिस्ट में विजय इंदर सिंगला का नाम टॉप पर हैं। हालांकि, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गुरुवार को राज्य पार्टी नेतृत्व में संभावित बदलाव की अटकलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि कुछ मामले

अंदरूनी होते हैं। जब उनसे इस अटकल के बारे में पूछा गया कि क्या वह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो वडिंग ने कहा कि मैं किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_SanjayS

जिद... सच की

चुनाव आयोग में पारदर्शिता जरूरी, आरोपों पर दे जवाब

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगातार विपक्षी नेताओं द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके इस्तीफे को पूरा विपक्षी गठबंधन एकजुट है। हालांकि विपक्ष की मांग उचित है। उन पर लगे आरोपों को सीईसी को खुद आगे बढ़कर बताना चाहिए कि सत्य क्या है। उनके दुलमुल रवैये से इस संवैधानिक संस्था की साख को बट्टा ही लग रहा है। आपको बता दें आंतरिक मतभेदों और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसलों को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसके सदस्यों के बीच अलग राय और विचार होना बातचीत का एक सामान्य हिस्सा था और सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। कामकाज के तरीकों को लेकर चुनाव आयोग हाल के बरसों में लगातार विवादों में रहा है। विपक्ष का उस पर अविश्वास इतना गहरा शायद कभी नहीं रहा, जहां उसके तमाम फैसलों पर संदेह जताया गया। ऐसे में आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ा जो खुलासा हुआ है, वह गंभीर सवाल खड़े करता है।

चुनाव आयोग का कहना है कि उसके सदस्यों के बीच अलग राय और विचार होना बातचीत का एक सामान्य हिस्सा था और सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। आयोग का यह भी कहना है कि 10 महीने की कुछ आंतरिक टिप्पणियों को अलग करके देखने से पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। चुनाव आयोग के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके तर्क सही लगते हैं। यह कतई जरूरी नहीं है कि किसी मामले में तीनों आयुक्तों की राय एक जैसी हो। संस्थान के भीतर असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। अलग-अलग विचार सामने आने पर ही बेहतर विकल्प का रास्ता खुलता है। हालांकि विभिन्न विचारों का फायदा तभी मिलता है, जब उन्हें सुना जाए। आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि किन असहमतियों पर विचार हुआ, किनको स्वीकार किया गया और किन पर एक राय बनाने की कोशिश हुई। यह सब इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला SIR, मतदाताओं के नाम हटाने-जोड़ने और उस डिजिटल सिस्टम से जुड़ा है, जिस पर इलेक्टोरल रोल निर्भर है। एसआईआर बेहद ही संवेदनशील मसला है। बिहार में इसकी शुरुआत से लेकर दिल्ली तक, कई बार इसे लेकर असंतोष जताया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में तो विवाद अभी तक शांत नहीं हुआ है। इस घटना से विपक्ष के आरोपों को बल मिलेगा और SIR को लेकर शंका बढ़ेगी, बल्कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर ही दी है। जब इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जारी हो, तब इतने किंतु-परंतु ठीक नहीं हैं।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

घटती जन्म दर से उभरता चिंताजनक परिदृश्य

डॉ. रितु सारस्वत

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने 'द घोस्ट ऑफ पॉपुलेशन पास्ट हाउ पॉपुलेशन कंट्रोल परसिस्ट्स इन इंडिया' नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की प्रजनन दर जरूरी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें तो राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.6 रह जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण को सरकारी नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में देखना प्रासंगिक नहीं है। साथ ही, परिवार नियोजन की नीतियों को स्वास्थ्य, बच्चों के बीच अंतर रखने और व्यक्ति की निजी पसंद के अनुरूप रखने की बात कही गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करने और चीन की जनसंख्या नीति से सबक लेने की भी सिफारिश की।

हालिया 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6' के आंकड़े भी अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निम्न प्रजनन दर की स्थिति की ओर संकेत करते हैं। अमूमन यह समझना सहज नहीं है कि आखिर यह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मूल रूप से यह है क्या। इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सहज उत्पन्न होगा कि 2.1 यानी एक महिला 2.1 बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? इसे समझने के लिए पहले प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर, दोनों को समझना होगा। प्रजनन दर का सीधा अर्थ है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। वहीं, प्रतिस्थापन स्तर वह स्थिति है, जिसमें एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से संख्या के स्तर पर लगभग स्वयं को प्रतिस्थापित कर सके। सामान्यतः कम मृत्यु दर वाली आबादी

में यह स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है। यानी 2.1 का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक महिला के 2.1 बच्चे हों, बल्कि यह पूरी आबादी में महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए बच्चों का औसत है। यह स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसके नीचे बनी रहती है तो आने वाली पीढ़ी का आकार धीरे-धीरे छोटा होने लगता है।

इसका असर आगे चलकर आबादी की आयु संरचना तथा कार्यशील आबादी के आकार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जनसंख्या में एक संतुलन का होना महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत की आबादी अब अचानक घटने



लगेगी। कम प्रजनन दर का प्रभाव कुल आबादी में दिखाई देने में कई दशक लग सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बड़ी संख्या में युवा आबादी मौजूद है और जनसांख्यिकीय जड़त्व के कारण कुछ समय तक आबादी बढ़ती रह सकती है। लेकिन यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसी तरह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) से नीचे बनी रहती है तो आगे चलकर आबादी के आकार के साथ-साथ उसकी आयु संरचना में भी बड़ा बदलाव आएगा। एनएफएचएस-6 के हालिया आंकड़े इस बदलाव की गंभीरता को समझने का एक संकेत देते हैं। अंडमान-निकोबार में कुल प्रजनन दर 0.9 तक पहुंच गई है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी यह प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती

है तो आने वाले समय में भारत के सामने केवल आबादी के आकार का नहीं, बल्कि वृद्ध होती आबादी, घटती कार्यशील आबादी और बदलती सामाजिक संरचना का प्रश्न भी खड़ा होगा। इसलिए यह ऐसा विषय है, जिस पर भविष्य की स्थिति का इंतजार करने के बजाय अभी से गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। आखिर प्रजनन दर में इस गिरावट के पीछे कारण क्या हैं? इसके कारणों को केवल जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में तलाशना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे समाज में पिछले कुछ दशकों में आए उन बदलावों को समझना होगा, जिनका असर परिवार, विवाह, मातृत्व और बच्चों को लेकर हमारी सोच पर पड़ा है। महिलाओं की

शिक्षा इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा ने महिलाओं के सामने जीवन के विकल्पों का विस्तार किया है। उच्च शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने की क्षमता ने महिलाओं के जीवन की प्राथमिकताओं को बदला है।

विवाह और मां बनने का फैसला भी अब कई महिलाएं अपने जीवन की अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लेने लगी हैं। लेकिन इसे केवल इस रूप में देखना उचित नहीं होगा कि महिलाओं के शिक्षित होने के कारण बच्चे कम हो गए। शिक्षा ने महिलाओं में अपने जीवन, करियर और भविष्य को लेकर आकांक्षाएं बढ़ाई हैं तथा परिवार और मातृत्व को लेकर निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया है।

प्रोफेसर सुखदेव सिंह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पारित 'लिंग्डेस ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' पर हस्ताक्षर करने के बाद अब यह अमेरिकी कानून बन गया है। इससे राष्ट्रपति के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर निर्भर रहने से जुड़ी कानूनी जटिलताएं खत्म हो गईं। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को न केवल रूस व ईरान पर प्रतिबंध लगाने का हक देता है, बल्कि रूस के कुल वैश्विक तेल निर्यात का 15 प्रतिशत से अधिक आयात करने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का भी अधिकार देता है। रूसी तेल और गैस के शीर्ष खरीदारों में भारत और चीन शामिल हैं, तो यह कानून इनके लिए चेतावनी है। रूस की विश्व स्तर पर बिक्री से भारत 37 प्रतिशत और चीन 50 फीसदी तेल आयात करता है, जो उनकी आबादी की जरूरतों के लिए आवश्यक हैं।

बिल पारित होने के बाद भारत, चीन और रूस की कड़ी आपत्तियों और भारत द्वारा द्विपक्षीय संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों की चेतावनी के बावजूद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना किसी हिचकिचाहट हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। रूस के साथ गंभीर भू-राजनीतिक मतभेद होने के कारण, अमेरिका अपने और अपने सहयोगियों के लिए रूसी और ईरानी तेल का बहिष्कार करने वाले ऐसे कानून बना सकता है, लेकिन अमेरिका को अन्य संप्रभु देशों को उन देशों से अमेरिका को निर्यातों पर भारी टैरिफ लगाकर इस मुहिम में शामिल होने के लिए मजबूर करने का कोई हक नहीं। यह

ब्रिक्स देशों को नए अमेरिकी टैरिफ कानून की चुनौती



अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों के उलट है। वे अपनी आबादी की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे और किफायती स्रोतों से ऊर्जा पदार्थ आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार, अप्रैल और अगस्त 2026 के बीच कच्चे तेल का आयात 100,669 हजार मीट्रिक टन और एलपीजी का आयात 4,992 हजार मीट्रिक टन था। ट्रेडइंट के इम्पोर्ट डेटा और 'बिल ऑफ लैंडिंग' डेटाबेस से पता चलता है कि 2026 की शुरुआत में भारत ने अपने कच्चे तेल के कुल आयात में से इराक से 19.89 प्रतिशत, रूस से 17.92 प्रतिशत, सऊदी अरब से 16.03 प्रतिशत, यूएई से 11 प्रतिशत, न्यूजीलैंड से 6.95 प्रतिशत, ब्राजील से 5.04 प्रतिशत, अंगोला से 4.49 प्रतिशत, नाइजीरिया से 3.93 प्रतिशत, यूएसए से 3.51 प्रतिशत और कुवैत से 2.93 प्रतिशत कच्चा तेल खरीदा।

हालांकि, अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान इराक से होने वाली शिपमेंट में बड़ी रुकावटों के कारण अगस्त 2026 तक रूस से कुल इम्पोर्ट बढ़कर लगभग 45

प्रतिशत हो गया था। रूस की जगह अमेरिका खुद को तेल व गैस के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर पेश करता है। लेकिन भारत के लिए, अमेरिका से आने वाला कच्चा तेल न केवल रूस से आने वाले तेल से महंगा है, बल्कि भाड़े की लागत भी रूसी टैंकर रूट की तुलना में ज्यादा है।

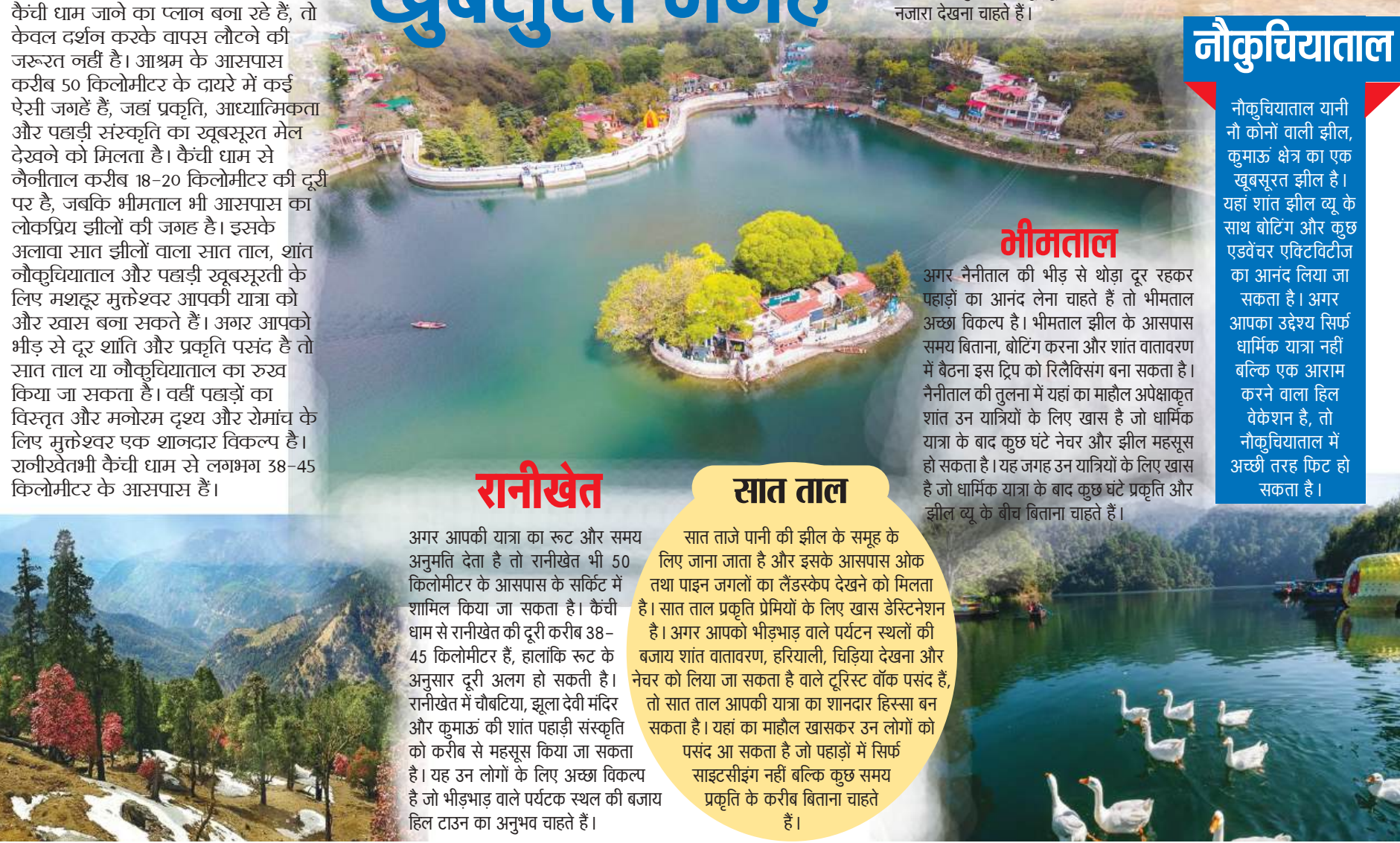
वहीं भारतीय रिफाइनरियां रूसी और मध्य-पूर्वी कच्चे तेल के लिए बनी हैं; अलग क्वालिटी वाला अमेरिकी तेल प्रोसेस करना चुनौती है। भारत सस्ते रूसी इम्पोर्ट छोड़ अमेरिकी महंगा तेल क्यों खरीदे? भारत अपने राष्ट्रीय हित में व्यापार के लिए वैश्विक ताकतों के बीच संतुलन बनाने के लिए 'रणनीतिक स्वायत्तता' की बात करता है, जबकि अमेरिका उसे अपनी नीतियों और भू-राजनीतिक योजनाओं के अनुसार चलने को मजबूर करता है। यह एक तरफ भारत व चीन के खिलाफ 'व्यापार को हथियार बनाने' और दूसरी तरफ रूस और ईरान के खिलाफ व्यापार युद्ध की राजनीति है। इस कानून का दिलचस्प पहलू है कि इसमें उन देशों को छूट दी गई है जो रूस के

कुल वैश्विक ऊर्जा निर्यात का 15 प्रतिशत से कम खरीदते हैं। इन देशों में जापान, फ्रांस, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की नीति का समर्थन करते हैं। रूसी तेल आयात का आकलन करने का तरीका भी एक राजनीतिक पहलू है किसी देश के कुल ऊर्जा आयात में रूसी ऊर्जा की हिस्सेदारी के प्रतिशत को देखने के बजाय रूस के कुल वैश्विक ऊर्जा निर्यात में उस देश का रूस से आयात प्रतिशत देखा जाता है। यूरोप सामूहिक रूप से रूस के वैश्विक गैस निर्यात का लगभग आधा हिस्सा लेकर रूसी गैस का सबसे बड़ा वैश्विक खरीदार है।

सवाल है कि अगर इस कानून का मकसद रूस के 'युद्ध कोष' को निर्यातित करना है, तो फिर 15 प्रतिशत की सीमा की शर्त क्यों? यूरोपीय देश काफी हद तक अमेरिकी नीति के साथ चलते हैं। नतीजन, उन देशों को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुसार और भारत के मुकाबले अमेरिकी तेल पर कम भाड़ा लागत होने से रूसी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदने में ज्यादा परेशानी नहीं है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मसूदा पेजेशिकयन की पूर्ण सदस्य के रूप में उपस्थिति, ब्रिक्स घोषणापत्र में एकतरफा दबाव वाले उपायों की निंदा, बहुपक्षवाद व बहु-ध्रुवीयता के प्रति प्रतिबद्धता, सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार, भुगतान और मैसेजिंग चैनलों के लिए सीमा-पार इंटरऑपरेबिलिटी, और ब्रिक्स की स्थानीय मुद्दाओं का उपयोग जैसे कारकों ने बिल को कानून का रूप देने की प्रक्रिया तेज की। यह कानून उन वैकल्पिक आर्थिक नेटवर्क पर सीधे हमला करने के हथियार के रूप में लाया गया है, जिन्हें मजबूत करने के लिए ब्रिक्स सदस्य प्रयास कर रहे हैं।

नीम करोली बाबा आश्रम के आसपास हैं ये खूबसूरत जगहें

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित कैंची धाम यानी नीम करोली बाबा आश्रम आज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, बल्कि आसपास की खूबसूरत पहाड़ियां, झीलें, जंगल और शांत हिल स्टेशन इसे एक शानदार यात्रा डेस्टिनेशन भी बनाते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा आश्रम या कैंची धाम जाने का प्लान बना रहे हैं, तो केवल दर्शन करके वापस लौटने की जरूरत नहीं है। आश्रम के आसपास करीब 50 किलोमीटर के दायरे में कई ऐसी जगहें हैं, जहां प्रकृति, आध्यात्मिकता और पहाड़ी संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। कैंची धाम से नैनीताल करीब 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि भीमताल भी आसपास का लोकप्रिय झीलों की जगह है। इसके अलावा सात झीलों वाला सात ताल, शांत नौकुचियाताल और पहाड़ी खूबसूरती के लिए मशहूर मुक्तेश्वर आपकी यात्रा को और खास बना सकते हैं। अगर आपको भीड़ से दूर शांति और प्रकृति पसंद है तो सात ताल या नौकुचियाताल का रुख किया जा सकता है। वहीं पहाड़ों का विस्तृत और मनोरम दृश्य और रोमांच के लिए मुक्तेश्वर एक शानदार विकल्प है। रानीखेत भी कैंची धाम से लगभग 38-45 किलोमीटर के आसपास हैं।



मुक्तेश्वर

मुक्तेश्वर अपने प्रसिद्ध शिव मंदिरों, हिमालयन व्यू और चौली की जाली जैसे स्पॉट के लिए जाना जाता है। यहां प्रकृति के बीच चहलकदमी, फोटोग्राफी और रोमांचक एक्टिविटीज का भी विकल्प मिलता है। यह उन यात्रियों के लिए खास तौर पर अच्छा विकल्प है जो कैंची धाम के स्पीच्युल अनुभव के बाद पहाड़ों का खुला और खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं।

नौकुचियाताल

नौकुचियाताल यानी नौ कोनों वाली झील, कुमाऊं क्षेत्र का एक खूबसूरत झील है। यहां शांत झील व्यू के साथ बोटिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लिया जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक आराम करने वाला हिल वेकेशन है, तो नौकुचियाताल में अच्छी तरह फिट हो सकता है।

भीमताल

अगर नैनीताल की भीड़ से थोड़ा दूर रहकर पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो भीमताल अच्छा विकल्प है। भीमताल झील के आसपास समय बिताना, बोटिंग करना और शांत वातावरण में बैठना इस ट्रिप को रिलैक्सिंग बना सकता है। नैनीताल की तुलना में यहां का माहौल अपेक्षाकृत शांत उन यात्रियों के लिए खास है जो धार्मिक यात्रा के बाद कुछ घंटे नेचर और झील महसूस हो सकता है। यह जगह उन यात्रियों के लिए खास है जो धार्मिक यात्रा के बाद कुछ घंटे प्रकृति और झील व्यू के बीच बिताना चाहते हैं।

रानीखेत

अगर आपकी यात्रा का रूट और समय अनुमति देता है तो रानीखेत भी 50 किलोमीटर के आसपास के सर्किट में शामिल किया जा सकता है। कैंची धाम से रानीखेत की दूरी करीब 38-45 किलोमीटर हैं, हालांकि रूट के अनुसार दूरी अलग हो सकती है। रानीखेत में चौबटिया, झूला देवी मंदिर और कुमाऊं की शांत पहाड़ी संस्कृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो भीड़भाड़ वाले पर्यटक स्थल की बजाय हिल टाउन का अनुभव चाहते हैं।

सात ताल

सात ताजे पानी की झील के समूह के लिए जाना जाता है और इसके आसपास ओक तथा पाइन जंगलों का लैंडस्केप देखने को मिलता है। सात ताल प्रकृति प्रेमियों के लिए खास डेस्टिनेशन है। अगर आपको भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों की बजाय शांत वातावरण, हरियाली, चिड़िया देखना और नेचर को लिया जा सकता है वाले टूरिस्ट वॉक पसंद हैं, तो सात ताल आपकी यात्रा का शानदार हिस्सा बन सकता है। यहां का माहौल खासकर उन लोगों को पसंद आ सकता है जो पहाड़ों में सिर्फ साइटसीइंग नहीं बल्कि कुछ समय प्रकृति के करीब बिताना चाहते हैं।



हंसना मना है

डॉक्टर: जब आपको पता था, छिपकली आपके नाक में जा रही है, तो आपने रोका क्यों नहीं? मरीज: पहले कॉकरोच गया था, मैंने सोचा उसे पकड़ने जा रही होगी।

वाइफ: सुबह मेरे चेहरे पे पानी क्यों डाला? हसबैंड: तेरे बाप ने कहा था, मेरी बेटी फुल की तरह है इसे मुरझाने मत देना।

पप्पू: बताओ वो कौन सी औरत है जिसको सौ प्रतिशत पता होता है की उसका हसबैंड कहां हैं? पप्पू ने अपना खतरनाक दिमाग लगाया और बोला, विधवा औरत।

पापा: नालायक, तुमने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात क्यों की? बेटा: मुझे पता है पापा आपको जलन हो रही है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते।

आदमी: सर, मेरी वाइफ गूम गई है, पोस्टमन: यह पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं, आदमी: ओह सॉरी! साला खुशी के मारे कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा!

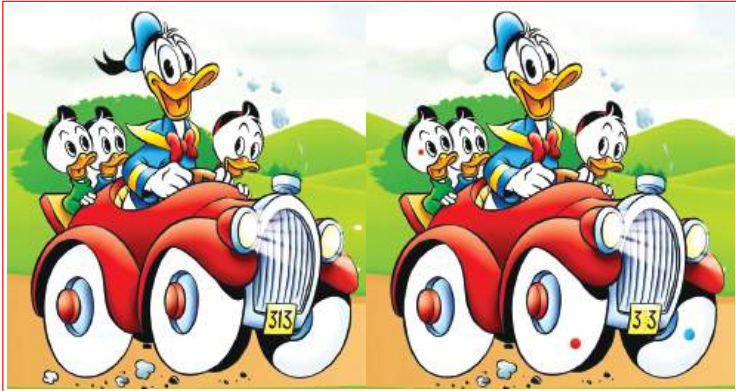
टीचर- डेट और तारीख में क्या अंतर है? सारी पूरी क्लास चुप, गप्पू- सर, डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ।

कहानी

बैल और शेर

एक जंगल में तीन बैल रहा करते थे। तीनों आपस में अच्छे मित्र थे। वो घास चरने के लिए जंगल में एक साथ ही जाया करते थे। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था। शेर इन तीनों को मारकर खा जाना चाहता था। उसने कई बार बैलों पर आक्रमण भी किया, लेकिन बैलों की आपसी मित्रता के कारण वो कभी सफल नहीं हो पाया। जब शेर उन पर हमला करता था, तो तीनों बैल त्रिकोण बनाकर अपने नुकीले सींगों से अपनी रक्षा करते थे। तीनों बैल साथ मिलकर कई बार शेर को भगा चुके थे। शेर यह समझ गया था कि जब तक ये तीनों साथ रहेंगे, इन्हें मारा नहीं जा सकता है। इसलिए, उसने एक दिन इन तीनों को अलग करने के लिए एक चाल चली। शेर ने बैलों को अलग करने के लिए जंगल में एक अफवाह उड़ा दी। अफवाह यह थी कि इन तीनों बैलों में से एक बैल अपने साथियों को धोखा दे रहा है। बस फिर क्या था, बैलों के बीच इस बात को लेकर शक बैठ गया कि आखिर वो कौन है, जो हमें धोखा दे रहा है? एक दिन इसी बात को लेकर तीनों बैलों में झगड़ा हो गया। शेर ने जो सोचा था, वो हो गया था। अब तीनों बैल अलग-अलग रहने लगे थे। उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। अब वो अलग-अलग होकर जंगल में चरने जाने लगे थे। बस शेर को इसी मौके का इंतजार था। शेर ने एक दिन उन तीनों बैलों में से एक पर हमला बोल दिया। अकेले पड़ जाने की वजह से वह बैल शेर का मुकाबला नहीं कर पाया और शेर ने उसे मार डाला। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल पर भी हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। वह समझ गया था कि शेर अब उसको भी मार डालेगा। उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन जब वह जंगल में घास चरने गया था, तो शेर ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। शेर की चाल पूरी तरह कामयाब हुई और उसने तीनों बैलों की दोस्ती तोड़कर उन्हें अपना शिकार बना लिया था।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

मेष 	नौकरी में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा। व्यापार में लाभ की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। परिवार में बड़ों के आशीर्वाद से रुके काम बनेंगे। सुबह टहलना शुरू करें।	तुला 	कार्यक्षेत्र में आपकी बोली और व्यवहार की प्रशंसा होगी। व्यापार में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा।
वृषभ 	कार्यस्थल पर नई योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में साझेदारी से बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।	वृश्चिक 	कार्यस्थल पर आपकी नई सोच को स्वीकार किया जाएगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं, प्रयास तेज करें। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता और मिटास आएगी।
मिथुन 	परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर लाभ कमाएं। अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा।	धनु 	कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, योजनाओं को गुप्त रखें। व्यापारिक खर्च बढ़ सकते हैं, संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में संयम और शांति रखें।
कर्क 	कार्यक्षेत्र में आपकी एकग्रता से परिणाम अच्छे आएंगे। व्यापार में दूरगामी सोच से मुनाफा कमा सकते हैं। संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।	मकर 	नौकरी में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार में अपेक्षित लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ सुखद मुलाकात हो सकती है। आंखों में जलन या तनाव हो सकता है।
सिंह 	कार्यस्थल पर वाद-विवाद से दूर रहना ही समझदारी है। व्यापारिक सोदों में जल्दबाजी न करें, समीक्षा करें। घर में छोटी बातों पर तूल न दें, शांति रखें।	कुम्भ 	करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। चुस्ती महसूस होगी।
कन्या 	आपकी कूटनीति से कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी। व्यापार में नए ऑर्डर या अनुबंध मिलने के संकेत हैं। भाई-बहनों से संबंध मधुर और मजबूत होंगे।	मीन 	धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मानसिक शांति मिलेगी, सेहत उत्तम रहेगी।

पाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू

हुमा कुरैशी की फिल्म बेबी डू डाई डू 3 जुलाई 2026 को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी चर्चा थी, लेकिन सिनेमाघरों में आने के बाद इसे दर्शकों का कुछ खास रिसर्पॉन्स नहीं मिला। बेबी डू डाई डू बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। थिएटर के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। वहीं ओटीटी पर ये फिल्म खूब देखी जा रही है। बेबी डू डाई डू को 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और ये पाकिस्तान में छा गई है। फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर

23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर किया गया था रिलीज

रहे हैं। हुमा कुरैशी की ये फिल्म पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में एक वीक से नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है। पाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म, नेटफ्लिक्स पर बेबी डू डाई डू बनी नंबर 1 इसने लस्ट ल्टोरीज 3, इरुमुडी और धमाल 4 जैसी और भी कई फिल्मों को पछाड़ नंबर 1 पर कब्जा किया है। बेबी डू डाई डू एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म बेबी कर्मकार (हुमा कुरैशी) नाम की एक बोल और सुन न सकने वाली लड़की की कहानी है, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करती है। इस खामोश जिंदगी के पीछे उसका मकसद अपने बचपन में मारी गई बहन की मौत का बदला लेना होता है। 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म के सरपेंस भी है, जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा।



फिल्म की कास्ट

फिल्म में हुमा कुरैशी के अलावा सिकंदर खेर, चंकी पांडे	और रचित सिंह जैसे कलाकार भी हैं। imdb पर बेबी डू डाई डू को 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो हुमा कुरैशी हालिया रिलीज फिल्म पूजा मेरी जान में आ रही हैं, जो 2 अक्टूबर को जी5 पर रिलीज हुई है। फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी लीड रोल में हैं। इससे पहले वो यश की फिल्म टॉक्सिक में भी नजर आई थी। फिल्म को थिएटर्स में कुछ खास रिसर्पॉन्स नहीं मिला।	

जूनियर एनटीआर अब अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। एक्टर ने इस पोस्ट के जरिए देवरा: पार्ट 1 में जाहवी कपूर के साथ अपने मशहूर गाने चुड़मल्ले के विजुअल्स में छेड़छाड़ करके बनाए गए एआई-जनरेटेड वीडियो के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मॉर्फ और एआई जनरेटेड वीडियो को घिनौना बताते हुए वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने वालों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ-साफ शब्दों में कहा है कि वह इस वीडियो के पीछे और इसे फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं।

जूनियर एनटीआर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस विलप पर प्रतिक्रिया देते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वीडियो को घिनौना और शर्मनाक बताते हुए, एक्टर ने सवाल उठाया कि किसी आखिर महिला से जुड़े ऐसे गलत और अपमानजनक कंटेंट को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे।

एक्टर ने मॉर्फ वीडियो के पीछे के लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा- घिनौना, बीमार मानसिकता वाला और शर्मनाक। जिस देश में महिलाओं को मां का दर्जा दिया जाता है और देवी के रूप में पूजा जाता है, एक ऐसा देश जहां मातृदेवो भव सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है, वहां कुछ लोग इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक महिला का बहुत ही अपमानजनक तरीके से अनादर कर रहे हैं। AI का इस्तेमाल करके ऐसी घिनौनी चीज बनाना बेहद शर्मनाक और दुखद है।



जाहवी कपूर संग मॉर्फ वीडियो देख जूनियर एनटीआर का पारा हुआ हाई

अपने पोस्ट में जूनियर एनटीआर ने ऐसे वीडियो और कंटेंट को बढ़ावा न देने की भी अपील की है। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, सॉन चुड़मल्ले के इस एआई-मॉर्फ वीडियो के पीछे जो भी घटिया लोग हैं, मैं उनसे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस वीडियो को बनाने वाले और इसे फैलाने वालों के खिलाफ हर संभव कानूनी कार्रवाई करूंगा। कृपया इस तरह के कंटेंट को न देखें, न शेयर करें और न ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दें। ये आज किसी और महिला के साथ हो रहा है, कल को आपकी मां, बहन पत्नी या बेटी के साथ हो सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। मैं सभी राज्य की सरकारों और भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वे इस तरह एआई का गलत इस्तेमाल न होने दें और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएं और कड़े नियम लागू करें।



अर्चना पूरन सिंह ने मड आइलैंड में खरीदा नया बंगला, गोवा से कम नहीं है नजारा

अर्चना पूरन सिंह और उनके परिवार ने मड आइलैंड में अपने घरों के कलेक्शन में एक और बंगला शामिल किया है। एक्टर से ब्लॉगर बनीं अर्चना ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर इस नई प्रॉपर्टी को दिखाया। इसमें उनके पति परमीत सेटी, बेटे आर्यमान और आयुष्मान और परिवार के सदस्यों ने दर्शकों को घर की पूरी झलक दिखाई। यह नया बंगला परिवार के मौजूदा घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है, जहां अर्चना और परमीत अपने बेटों और उनके पार्टनर के साथ रहते हैं। अर्चना की मां और परमीत के पिता भी इसी घर में रहते हैं।



और किचन है। परिवार ने बताया कि किचन उनके फूड कंटेंट की शूटिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। योगिता ने यह भी बताया कि ब्लॉगर्स का परिवार नया घर सेट-अप करने के मामले में कितना अलग सोचता है। उन्होंने कहा कि जहां ज्यादातर लोग सबसे पहले यह सोचते हैं कि उनका फर्नीचर कहाँ रखा जाएगा, वहीं उनकी पहली चिंता यह थी कि कैमरे कहाँ लगाए जा सकते हैं। परिवार ने इस बात पर भी चर्चा शुरू की कि बंगले का इस्तेमाल वर्कस्पेस के तौर पर कैसे किया जा सकता है। योगिता इसका इस्तेमाल अपने वीडियो शूट करने के लिए कर सकती थीं, जबकि समीक्षा इसी प्रॉपर्टी से अपनी योग क्लास ले सकती थीं। अर्चना को एक और आइडिया आया — घर की तीनों महिलाओं के लिए एक कमरे को वॉक-इन क्लोजेट में बदलना। बंगले में तीन बेडरूम हैं, और हर बेडरूम के साथ एक अटैच बाथरूम है। कई बड़ी खिड़कियों से घर के अंदर भरपूर नैचुरल रोशनी आती है, और प्रॉपर्टी के चारों ओर हरियाली है। बाहर एक गार्डन और एक गजेबो है, साथ ही घर में दो बालकनी और एक बड़ी सीढ़ी भी है।

प्रीति जिंटा ने हाल ही में सनी देओल की पीरियड ड्रामा फिल्म बंटवारा 1947 से आठ साल के ब्रेक के बाद एक्टिंग में वापसी की है। वह 2018 के आस-पास लाइमलाइट से दूर हो गई थीं ताकि अपनी पर्सनल जिंदगी पर ध्यान दे सकें और अमेरिका में अपने पति जीन गुडइनफ के साथ अपने जुड़वां बच्चों की परवरिश कर सकें। अब, एक हालिया इंटरव्यू में प्रीति ने एक स्टार के तौर पर सबका ध्यान खींचने और फिर घर पर सीमित मदद के साथ एक होममेकर की जिंदगी जीने के अपने अनुभव को याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने गूगल और विकिपीडिया को लीगल नोटिस भेजा था, क्योंकि बॉबी देओल द्वारा दिया गया उनका एक मजाकिया निक्नेम इतना मशहूर हो गया था कि बहुत से लोग उसे ही उनका असली नाम समझने लगे थे। प्रीति को यह साफ करने के लिए लीगल नोटिस भेजना पड़ा कि उनका असली नाम प्रीति है, प्रीतम सिंह नहीं। बॉम्बे टाइम्स के साथ बातचीत में, प्रीति जिंटा से पूछा गया कि क्या ब्रेक लेने के बाद उन्हें बॉलीवुड की ग्लैमरस जिंदगी की याद आती है। उन्होंने कहा, उस माहौल में ढलने के लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत थी। जब मैं एक्टिंग करती थी, तो सब कुछ मेरे आस-पास ही घूमता था। सारा ध्यान मुझ पर होता था—मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ। फिर मैं क्रिकेट से जुड़ी और सीखा कि मैं क्या कर रही हूँ, इससे ज्यादा जरूरी खेल पर ध्यान देना था।

...जब प्रीति जिंटा ने गूगल को भेजा था कानूनी नोटिस

दृश्यम 3 ने तीसरे दिन 173 करोड़ के पार किया कलेक्शन

दृश्यम 3 से अजय देवगन छ छ गए हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर अजय की एक्टिंग तक ने धमाल मचा दिया है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और खूब तारीफ हो रही है। फिल्म को 2 अक्टूबर की छुट्टी का भी फायदा मिला। दो दिन में फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी और अब तीसरे दिन भी शानदार कलेक्शन कर रही है।

सैकनलिक के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को 9।30 बजे तक 57.79 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म को 16,418 शोज मिले और 56 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म ने टोटल नेट 173.29 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने ग्राँस 206.79 करोड़ की कमाई की। पहले दिन फिल्म ने 62 करोड़ कमाए। फिल्म को



15,759 शोज मिले और फिल्म को 60.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म ने दूसरे दिन 53.50 करोड़ की कमाई की। फिल्म को 16,868 शोज मिले और 48.1 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली। फिल्म को अभिषेक पाठक

ने डायरेक्ट किया। फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं। वो विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आए। वहीं फिल्म में अजय देवगन, तबु, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, रजत कपूर जैसे स्टार्स दिखे।

भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में 4पीएम की गूंज

- » इंदौर में 22 राज्यों के प्रेस क्लब जुटे
- » शाहीन-नफीसा खान से लेकर भिंड के पत्रकारों पर हमले तक उठे सवाल?
- » संजय शर्मा ने मीडिया पर बढ़ते दबाव की रखी तस्वीर

पत्रकारों पर हमलों के खिलाफ साझा लड़ाई का संकल्प



4पीएम संपादक संजय शर्मा ने रखी मीडिया की तस्वीर



भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित अखण्ड की दौड़ कक्षा तक सत्र में 4पीएम के प्रमुख संजय शर्मा विशेष वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए कहा कि पत्रकारिता के सामने मौजूद चुनौतियों सत्ता और मीडिया के संबंध तथा सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर बढ़ते दबाव मौजूदा समय की चुनौतियां हैं जिन्हें हम स्वीकार कर आगे बढ़ना है और अपनी बात रखनी है। उन्होंने कामकाज के दौरान सामने आई चुनौतियों और चैनल पर हुई कार्रवाइयों का सिलसिलेवार निष्कर्ष करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद 4पीएम ने अपनी पत्रकारिता और सवाल पूछने की आजादी निरंतर रखी उन्होंने 4पीएम के सफर से जुड़े अपनी संघर्षशील पत्रकारिता के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि पत्रकारिता की ताकत सिर्फ खबर प्रकाशित करने में नहीं बल्कि सवाल पूछने और असुविधाजनक मुद्दों को सामने लाने की क्षमता में है। संजय शर्मा ने 4पीएम चैनल पर हुई कार्रवाइयों का निष्कर्ष करते हुए कहा कि सरकार ने पूरी ताकत के साथ दमनात्मक कार्रवाई की। चैनल को बंद किया गया जबकि नाम पर इशारा गया लेकिन 4पीएम कभी डर नहीं घबरायी नहीं हम कोर्ट गये और वहां से हमें न्याय मिला। इसलिए सच की राज में जब कभी भी सरकार आप पर कार्रवाई करे या फिर इशारे तो डरिये मत डट कर मुकाबला कीजिए।

शाहीन और नफीसा की कहानी ने खींचा ध्यान

संजीव श्रीवास्तव/4पीएम न्यूज़ नेटवर्क इंदौर। देशभर के पत्रकार जब इंदौर में एक मंच पर जुटे तो चर्चा सिर्फ पत्रकारिता की चुनौतियों तक सीमित नहीं रही। सवाल उन हालात पर भी उठा जिनमें खबर करने वाले पत्रकार ही सत्ता पुलिस और प्रभावशाली लोगों के दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी बहस के केंद्र में रहा 4पीएम और उसकी पत्रकारिता। स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश के तीन दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के 18वें संस्करण में देश के 22 राज्यों के प्रेस क्लबों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 2 से 4 अक्टूबर तक चले आयोजन में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

सार्क मीडिया फोरम की भागीदारी ने इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया। नेपाल से फोरम के अध्यक्ष राजू लामा बांग्लादेश से महासचिव अब्दुर रहमान और फॉरेन कॉरिस्पोंडेंट प्रेस क्लब नई दिल्ली के महासचिव प्रकाश नंदा समेत देशभर के पत्रकार और मीडिया प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक मुद्दा बार बार सामने आया और वह मुद्दा था दिल्ली में रिपोर्टिंग के दौरान 4पीएम के पत्रकारों पर

हमला। और इस पूरे प्रकरण के अनुभव चर्चा के केंद्र में रहे। फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स के मंच पर 4पीएम की दिल्ली संवाददाता शाहीन खान और सोशल मीडिया जर्नलिस्ट नफीसा खान ने सितंबर में दिल्ली में रिपोर्टिंग के दौरान अपने साथ हुई पुलिस कार्रवाई का अनुभव साझा किया। 3 सितंबर को रिपोर्टिंग के दौरान हुई घटना को लेकर दोनों ने मंच से अपना पक्ष रखा। पत्रकारों ने अपनी आपबीती सुनाई। आयोजन में 4पीएम के संपादक संजय शर्मा की ओर से दोनों पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख हुआ। मंच पर मौजूद



पत्रकारों ने इस पूरे प्रकरण को सिर्फ दो पत्रकारों का मामला नहीं माना बल्कि रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े बड़े सवाल के रूप में चर्चा की।

भिंड के पत्रकारों ने भी सुनाई संघर्ष की कहानी

मध्यप्रदेश के भिंड में रेत खनन से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हुए हमले का मुद्दा भी महोत्सव में चर्चा का विषय बना। भिंड के पत्रकार अमरकांत चौहान और शशिकांत गोयल ने भी मंच से अपने अनुभव साझा किए। दोनों ने रेत खनन से जुड़े गवर्नर और पत्रकारों पर हुई कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। दोनों पत्रकारों ने बताया कि इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग को 4पीएम द्वारा प्रमुखता दिए जाने से उनकी आवाज व्यापक स्तर तक पहुंची। उन्होंने पत्रकारों को मिले मार्गदर्शन और सहयोग के लिए स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि प्रकरण ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से मिली कानूनी सहायता से मदद मिली।

डॉ. उत्कर्ष सिन्हा ने खूब बटोरी तालियां

सूची के ख्यातनाम पत्रकार, चिंतक-लेखक, विचारक और टिप्पणीकार डॉ. उत्कर्ष सिन्हा भी आयोजन का हिस्सा रहे। क्लब के 'अखण्ड की दौड़ कक्षा तक' सत्र के वक्ता के तौर पर अपने धारदार विचारों से डॉ. सिन्हा ने दर्शकों की जबरदस्त तालियां बटोरीं। अन्य सत्र के विषय 'राजनीति की दाई-बाईं करवट' में डॉ. सिन्हा के साथ-साथ 4पीएम के कार्यक्रमों में विशेष मेहमान रहने वाले दिनेश के रोह्य और फ्री लॉस जर्नलिस्ट रवींद्र सिंह श्योराण ने भी अपने ओजस्वी एवं प्रभावशाली विचारों से समं बांधा। इनके विचारों को श्रोताओं ने नुक्त कंठ से सराहा। 4 पीएम के मध्यप्रदेश के संपादक एवं स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश के कार्यक्रम समन्वयक संजीव श्रीवास्तव ने विभिन्न सत्रों का संचालन किया।



मीडिया संस्थानों पर बढ़ते दबाव को लेकर चर्चा

मीडिया संस्थानों पर बढ़ते दबाव को लेकर चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने कहा कि पत्रकारों को लड़ाई मिलकर लड़नी होगी वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने पत्रकारों पर होने वाले हमलों और अन्याय के मामलों को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय इनके खिलाफ साझा मंच तैयार करने की जरूरत बताई। गर्ग ने कहा कि पत्रकारों और मीडियाकर्मीयों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के

मामलों में पत्रकार संगठनों को एकजुट लेकर पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके इस आह्वान ने कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न प्रेस क्लबों के प्रतिनिधियों के बीच पत्रकार सुरक्षा को लेकर साझा रणनीति की चर्चा को आगे बढ़ाया। फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स के अध्यक्ष और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष गौतम लाहिरी ने फेडरेशन की आगामी गतिविधियों और तैयारियों की जानकारी दी। वहीं अपने संबोधन में श्रवण गर्ग ने आह्वान किया। 'फेडरेशन, पत्रकारों पर अन्याय

अत्याचार की लड़ाई की संयुक्त रणनीति बनाए। पीडित पत्रकारों एवं मीडियाकर्मीयों की लड़ाई को पूरी ताकत से लड़े।' फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स के अध्यक्ष एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष गौतम लाहिरी ने फेडरेशन की भावी तैयारियों एवं रणनीति की तस्वीर पेश की। इस आयोजन में जेन-जेड और अल्फा पीढ़ी तथा पत्रकारिता पर इसके प्रभाव को समर्पित था। देशभर से 150 से अधिक वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और डिजिटल मीडिया पेशेवर शामिल हुए।



24 पत्रकारों को मिला सप्तऋषि सम्मान

महोत्सव के दौरान मध्यप्रदेश के 12 पत्रकारों को राज्य स्तरीय और देश के 12 मीडिया कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर के सम्मान से नवाजा गया। समापन समारोह में मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विपक्ष के नेता और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन 4पीएम के मध्यप्रदेश संपादक एवं भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के कार्यक्रम समन्वयक संजीव श्रीवास्तव ने विभिन्न सत्रों में किया। बड़ा सवाल यही रहा कि खबर लिखने वाला जब खुद खबर बन जाए तब उसके साथ कौन खड़ा होगा इंदौर के नय से इस सवाल का जवाब एक आवाज में सुनाई दिया कि पत्रकार अकेला नहीं होना चाहिए। पत्रकार पर हमला हो तो पत्रकार बिरादरी को उसके साथ खड़ा होना होगा।

पत्रकारों की कानूनी लड़ाई के लिए बनेगा समूह

फेडरेशन ऑफ प्रेस क्लब्स आयोजन के विशेष अतिथि एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमय दुबे ने एलान किया कि पत्रकारों के खिलाफ अन्याय और अत्याचार के मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समूह बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पत्रकारों और मीडियाकर्मीयों के साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रयास किए जाएंगे। दुबे ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमिषेक मजूमदार की अगुवाई में वरिष्ठ वकीलों का एक समूह तैयार किए जाने की घोषणा भी की। अमय दुबे के इस एलान से पत्रकारों की कानूनी सुरक्षा के सवाल को एक नया आयाम दिया।

पीढ़ी परिवर्तन की बेला है: मप्र विधानसभा अध्यक्ष तोमर

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं समझता हूं कि वर्तमान समय पीढ़ी के परिवर्तन की बेला है। इस बेला में हम सबको अपने मन का दायरा बढ़ाना चाहिए, नये आयामों पर दृष्टि डालनी चाहिए और जो पीढ़ी भविष्य में हमसे 'चांज' (कमान) लेने वाली है, उसका स्वागत-अभिनंदन करना चाहिए। विस अध्यक्ष कहा कि पुरानी और नयी पीढ़ी के बीच सोच का अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा मानने का कोई कारण समझ नहीं आता कि नयी पीढ़ी गलत दिशा में ही सोचेगी। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपराएं परिवर्तन को प्रकृति का नियम मानती हैं और हर कालखंड में बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहा है। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 'जेन-जी' के बजाय 'तरुण भारत' शब्द के इस्तेमाल की वकालत की है। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक परंपराओं के मुताबिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है और नयी पीढ़ी का खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए। 'जेन-जी' (जेनरेशन जेड) से तात्पर्य उस पीढ़ी से है जिसका जन्म मुख्य रूप से वर्ष 1997 से 2012 के बीच हुआ है। तोमर ने इंदौर में स्टेट प्रेस क्लब के भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में कहा कि निश्चित रूप से आज जेन-जी की बात सभी तरफ होती है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर हम 'जेन-जी' के बजाय 'तरुण भारत' शब्द का उपयोग करें, तो यह ज्यादा उत्तम होगा। उन्होंने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी देश-दुनिया में ऐसे चमत्कार कर रही है जो सबके लिए आश्चर्यजनक हैं।

राजधानी पानी-पानी...राहत को ढूँढती जिंदगानी

» राजधानी में रौद्र रूप में आई गोमती नदी

» कई इलाकों में जीवन ठहरा खाने तक के लिए मारा-मारी, घरों के आंगन तक पहुंची नावें

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क/क्षितिजकांत

लखनऊ। पानी जीवन है पर जब पानी हद से ज्यादा आ जाए तो वह जीवन को तकलीफों के समुंदर में डुबो देता है। पानी का प्रलय यूपी की राजधानी लखनऊ में अक्टूबर में दिखाई दे रहा है। जहां एआई और स्मार्ट सिटी के दावे करने वाले सत्ताधीशों को आम आदमी की बेबसी नहीं दिखाई दे रही है। पानी ने ऐसे घेरा है जैसे राजधानी नहीं लोग टापू में रह रहे हों। न तो खाना मिल रहा न पानी, न ही बीमार होने पर दवाई। प्रशासन व शासन बाते बड़ी-बड़ी कर रहा है। पर आम आदमी अब भी पानी के बीच सरकार को टकटकी लगा निहार रहा है।

वहीं तस्वीरें लोगों का दर्द बयां कर रही हैं। पानी घरों के आंगन तक पहुंच गया है लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो बुलडोजर लोगों को डरा रहा था वो भी आज राहत देने में जुटा दिखाई दिया। बता दें गोमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से दुबग्गा के जेहटा रोड समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। रविवार को शाम छह बजे तक जेहटा-माल रोड पर करीब डेढ़ फीट पानी बहने लगा था। माल और इटौंजा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक, अगले 24 घंटे में गोमती का जलस्तर दो फीट तक और बढ़ सकता है। प्रशासन की टीम ने हयात नगर मोड़, दौलतखेड़ा, सैथा और बरावन कला समेत प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। पहली मंजिल पर रहने वालों को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट होने और



पानी बढ़ा तो लौट आया डीएम का काफिला

हयात नगर मोड़, दौलतखेड़ा और सैथा के निरीक्षण के बाद डीएम का काफिला गुलमीखेड़ा, टाड़खेड़ा और सुखलालखेड़ा की ओर गया, लेकिन रास्ते में जलभराव अधिक होने से लौटना पड़ा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी दिखी। सुरक्षा के लिए रात में पेट्रोलिंग बढ़ाने और दाऊद नगर में अतिरिक्त कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।



घर में पानी... कमरे में बंद जिंदगी

हाथों में बैग थामे तीन फीट पानी से गुजरकर सड़क पर पहुंची फैजुल्लागंज के नंदन चौराह पर रहने वाली एक महिला पांच दिन से पानी घटने का इंतजार कर रही थी। मुश्किलें बढ़ती गईं तो रविवार को सब्र जवाब दे गया। अब पति और बच्चों के साथ किराये के कमरे में रहेगी। दिन-प्रतिदिन बढ़ रही मुश्किलों से जूझ रहे कई परिवार घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। किसी ने 3500 तो किसी ने तीन हजार रुपये में किराये पर कमरा लिया है। अटल चौक के पास रहने वाले मोहम्मद शमीर की गली में तीन दिनों से पानी भरा है।

रविवार को पानी घर में घुस गया तो परिवार वाले बेघर हो गए। समीर ने 35 सौ रुपये पर त्रिवेणीनगर में कमरा लिया है। छह लोगों का परिवार एक ही कमरे में गुजर बसर करेगा। सिलिंडर और अन्य सामान लेकर पानी से निकल रहे शुभम भी किराये के कमरे में जा रहे थे। सुंदरलाल भी तीन दिन से पानी घटने का इंतजार कर रहे थे। कम होने के बजाय पानी बढ़ गया और मुश्किलें भी। मजबूरी में सुंदरलाल भी दूसरी जगह चले गए। गणेश विहार कॉलोनी के मनोज के घर में भी कई दिनों से पानी भरा है।

गर्भवती महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा

गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 10 नावों की सुविधा शुरू की गई है।

500 बीघा धान की पकी फसल डूबी

मंझौवा गांव में गोमती का पानी बढ़ने से करीब 500 बीघा धान की पकी फसल डूब गई। खीरा, लौकी और मिंडी की फसल को भी नुकसान हुआ। अजय की तीन बीघा खीरे की फसल डूब गई। वहीं जयकरन, इंद्रपाल, राजाराम, महेश और सरवन के घर भी बारिश से गिर गए।



करोड़ों का प्रेरणा स्थल पानी-पानी

गोमती का पानी प्रेरणा स्थल में अब भी भरा है। कार्यालय में पानी घुसने से रोकने के लिए गेट पर रेत की बोरियां लगाई गई हैं। वहीं, रविवार को यह पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा। आईआईएम मार्ग से कैरियर कॉलेज के पास फैजुल्लागंज जाने वाली सड़क पर करीब 100 मीटर तक तेज बहाव है।

हर ओर पानी... पेयजल का इंतजाम नहीं

फैजुल्लागंज में मामा चौराह, अटल चौक, गणेश विहार, नंदन चौराह और अन्य कालोनियों में हर ओर सिर्फ पानी ही नजर आता है। मगर घरों में फंसे लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। घर के नल से बद्बुदर पानी आ रहा है। सीमा ने बताया कि पीना तो दूर हाथ-मुंह भी नहीं धुला जा सकता। प्रदीप का कहना था कि पीने के पानी का वितरण हो रहा है, लेकिन उनके पास तक नहीं पहुंचा है। कई लोग जुगाड़ वाली नाव से नगर निगम के टैंकर से बारूटी में पानी भरकर ले जा रहे थे।

कई दिन से पानी में फंसी ममता और उनके पति आशीष रविवार को घर से थोड़ा बहुत सामान निकालकर कंट्रोल रूम के पास पहुंचे थे। गोद में एक साल का बच्चा भी था। करीब दो घंटे इंतजार के बाद भी नाव या ट्रैक्टर नहीं मिला। बेहाल बच्चे को लेकर ममता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाती रही। उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला।

बच्चा बेहाल मां की गुहार

अंतिम सफर में बाढ़ की मार

गोमती की बाढ़ से अब अंतिम सफर की राह भी मुश्किल हो गई है। गुलाला घाट के अंत्येष्टि स्थल में तीन दिन से नदी का पानी भरा है। रविवार को घाट जाने वाली सड़क पर करीब डेढ़ फीट पानी तेज बहाव के साथ बहता रहा। दोपहर करीब एक बजे एक शव वाहन घाट पहुंचा। चालक ने लोगों से पानी की स्थिति की जानकारी ली और धीरे-धीरे वाहन आगे बढ़ाया। बाद में शव को वाहन से उतारकर परिजन पानी से गुजरते हुए चबूतरे तक पहुंचे। अंत्येष्टि स्थल परिसर में भी करीब एक फीट पानी भरा है और यह लकड़ियों तक पहुंच गया है। घाट की व्यवस्था देखने वाले वीरेंद्र पांडे ने बताया कि पानी भरने से बिजली आपूर्ति बंद है, जिससे विद्युत शवदाह गृह भी बंद है।

महिला सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम फटकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा कि राजधानी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर महिला

पार्क, सड़क और बसों खतरे वाले इलाके न बनें

पिछली सुनवाई में अदालत ने साफ कहा था कि पार्क, सड़क और बस जैसी सार्वजनिक जगहों को ज्यादा जोखिम वाले इलाके बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या 2012 के निर्णय कांड से कोई सबक लिया गया है। अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले सम्मान के साथ जीने और हिंसा से मुक्त रहने के मौलिक अधिकार से भी जोड़ा।

सार्वजनिक जगहों और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते समय खुद को सुरक्षित महसूस करें। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एनसीटी दिल्ली में हर महिला सुरक्षित महसूस करें, चाहे वह रात 10 बजे पैदल चल रही हो या मेट्रो और सड़क के रास्ते सफर कर रही हो।

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में हाल में सामने आए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर स्वतः संज्ञान से शुरू की गई सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े कई मामलों का स्वतः संज्ञान लिया था। इनमें कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म, स्वरूप नगर में एक नाबालिग से कथित गैंगरेप और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही बस में 16 साल की लड़की के कथित यौन उत्पीड़न का मामला शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

» चुनाव आयोग के एकतरफा फैसलों के आरोप पर सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उन याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग ने दोनों

चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए। न्यायालय ने कहा कि जो भी फैसला कानून के अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को कोई भी फैसला लेने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहन का पीठ ने कहा कि वह उस कानूनी प्रावधान की भी जांच कर सकती है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद छोड़ने के बाद भी कानूनी संरक्षण देता है। पीठ ने कहा, हम सभी फैसलों की जांच करेंगे। यदि कोई फैसला कानून के अनुरूप नहीं पाया गया तो हम उसे रद्द कर देंगे। आप अदालत की शक्ति जानते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि सीईसी को हासिल कानूनी संरक्षण ऐसा है, जो न्यायाधीशों को भी प्राप्त



दिल्ली जिमखाना क्लब : विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करे हाईकोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों की याचिका पर विचार करने को कहा। इन सदस्यों ने क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को अपने कब्जे में लेने के केंद्र सरकार के फैसले और उसके बाद की बेदखली की कार्यवाई को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहन की बेंच को क्लब के सदस्यों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि केंद्र सरकार के फैसले को सिर्फ क्लब ही चुनौती दे सकता है। सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने सदस्यों से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्टीकरण ले लें कि क्या वे भी वहां याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि दूसरी पार्टी केस की स्वीकार्यता और अन्य कानूनी आपत्तियों के आधार पर विचार कर सकती है।

नहीं है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अंतरिम राहत के तौर पर ज्ञानेश कुमार को आगे कोई भी फैसला लेने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने सीईसी को निलंबित करने का भी अनुरोध किया और कहा कि हर नागरिक अपने मतदान के अधिकार को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है।

पीठ ने अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर संबंधित याचिका पर भी नोटिस जारी किया और उसे राकेश कुमार सिंह की याचिका के साथ जोड़ दिया।

दिल्ली दंगों से जुड़ी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं के पूरे समूह को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में नेताओं के खिलाफ कथित नफरती भाषण (हेट स्पीच) के लिए एफआईआर दर्ज करने, स्वतंत्र एक्सप्रेस का गठन करने और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं के समूह को दो हिस्सों में बांटा गया था – एक उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित और दूसरा जामिया मिलिया हिंसा से संबंधित। बेंच ने कहा, फैसले में बताई गई वजहों से, सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित याचिकाओं में राजनीतिक नेताओं के खिलाफ हिंसा के संबंध में कथित हेट स्पीच के लिए FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग भी शामिल थी। याचिकाओं में दंगों की जांच के लिए एक्सप्रेसआईटी जांच आयोग या फैक्ट-फाईंडिंग कमेटी बनाने की भी मांग की गई थी। कुछ याचिकाओं में हिंसा में शामिल होने के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ प्रभावित लोगों के इलाज और मुआवजे से संबंधित निर्देश देने की भी मांग की गई थी। इसलिए, राजनीतिक नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिकाएं 2020 के दंगों से संबंधित याचिकाओं के व्यापक समूह का हिस्सा थीं। हालांकि, हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाओं के इस समूह को खारिज कर दिया।